

प्रधान मंत्री जन धन योजना

भारत में 28 अगस्त, 2024 को प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई।

मुख्य बिंदु

- ❖ प्रधान मंत्री जन धन योजना की शुरुआत **वर्ष 2014** में की गई थी।
- ❖ इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित विशाल आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक नागरिक को अपनी वित्तीय गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का अवसर मिले।
- ❖ "बैंक रहित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना, वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करना और वंचितों की सेवा करना" के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस योजना ने पूरे देश में हर बैंकिंग सुविधा से वंचित परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- ❖ इस पहल ने देश के वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन गया है।

प्रभाव और प्रगति

इस योजना के एक दशक पूरे होने पर, इसके प्रभाव और प्रगति को उजागर करने वाले पाँच मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

- ❖ **व्यापक पहुंच और खाता वृद्धि** : अपनी स्थापना के बाद से, PMJDY ने 53.13 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं, जो मार्च 2015 से 3.6 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इन खातों में अब कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जो आठ वर्षों में 15 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
- ❖ **ग्रामीण और महिला लाभार्थियों पर ध्यान** : कुल खातों में से 29.56 करोड़ खाते महिला लाभार्थियों द्वारा खोले गए हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और वित्तीय पहुंच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।
- ❖ **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** : प्रधान मंत्री जन धन योजना खाताधारकों को कुल 36.14 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे नकदी रहित लेनदेन की सुविधा मिली है और अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर तक पहुंच मिली है। पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि 2,31,236 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाभार्थियों के बढ़ते भरोसे और वित्तीय गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
- ❖ **वैश्विक मान्यता** : प्रधान मंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है।



निष्कर्ष

भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के दस वर्ष पूरे होने पर यह स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम ने इस योजना ने देश के वित्तीय परिदृश्य को गहराई से बदल दिया है।

बैंक रहित लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने के अलावा, पीएमजेडीवाई ने 2014 में अपनी स्थापना के बाद से समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया है। 53 करोड़ से अधिक खाते खोले जाने, लगभग 30 करोड़ महिला लाभार्थियों, बड़ी जमाराशियों और बड़ी संख्या में RuPay डेबिट कार्ड जारी किए जाने के साथ, कार्यक्रम पूरे देश में फैल गया है, जिससे लाखों लोगों को सशक्त बनाया गया है, खासकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को।

एनआईसीडीपी के तहत परियोजनाएं

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नई परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

उद्देश्य

इन परियोजनाओं से देश के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव आएगा और औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनेगा, जिससे आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

- ❖ **शामिल राज्य :** ये स्वीकृत परियोजनाएँ 10 राज्यों में हैं और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है।
- ❖ ये परियोजनाएँ भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- ❖ **स्थान :** ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोपार्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।
- ❖ **रणनीतिक निवेश :** NICDP को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये औद्योगिक नोड 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जो एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- ❖ **स्मार्ट शहर और आधुनिक बुनियादी ढांचा :** नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं पर "मांग से आगे" बनाया जाएगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हैं जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं।
- ❖ **विकसित भारत' के लिए विजन :** इन परियोजनाओं की स्वीकृति 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

एसआई उत्खनन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 17 स्थलों पर उत्खनन करने जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- ❖ एसआई हरियाणा के राखीगढ़ी, दिल्ली के पूरन किला, उत्तर प्रदेश के बागपत के तिलवाड़ा और झांसी के राठ तथा बिहार के ताजपुर देउर में खुदाई करेगा।
- ❖ सिंधु-सरस्वती सभ्यता स्थल राखीगढ़ी, जिसने साबित किया कि आर्य भारत के बाहर से नहीं आए थे, की भी खुदाई की जाएगी। बिहार के चंपारण में बुद्ध स्तूपों की भी खुदाई की जाएगी।

- ❖ उत्तर प्रदेश में तिलवाड़ा स्थल और दिल्ली का पुराना किला महाभारत काल से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पुराना किला के आसपास ही थी। आजादी के बाद छठी बार यहां खुदाई की जाएगी।
- ❖ अहोम राजाओं और रानियों के दफन स्थल चराईदेव मैदाम, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, की भी खुदाई की जाएगी।
- ❖ उत्खनन के लिए सबसे अधिक आठ स्थल तमिलनाडु में हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकारें दो-दो स्थलों पर तथा असम सरकार एक स्थल पर उत्खनन करेगी।
- ❖ पश्चिम बंगाल में दो स्थलों, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और गुजरात में लोथल, जो कि सिंधु-सरस्वती सभ्यता का एक अन्य स्थल है, की भी एएसआई द्वारा खुदाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

- ❖ उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) के पर्यटक बंगलों को निजी उद्यमियों को 30 साल के पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

रिपोर्ट/सूचकांक

भारत सौर बाजार अद्यतन रिपोर्ट	<ul style="list-style-type: none"> ❖ रिपोर्ट को अमेरिका स्थित शोध फर्म मेरकॉम कैपिटल द्वारा प्रकाशित किया गया था। ❖ रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2024 की पहली छमाही में रिकॉर्ड 15 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी, जो 2023 की इसी अवधि की तुलना में 282% की वृद्धि को दर्शाता है, जो डेवलपर्स द्वारा विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने के कारण है। ❖ जून 2024 तक, भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 87.2 गीगावाट तक पहुँच गई, जिसमें उपयोगिता-स्तरीय परियोजनाएँ इस कुल का 87% हिस्सा बनाती हैं।
'वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, 2024'	<ul style="list-style-type: none"> ❖ इसे वैश्विक संपत्ति सलाहकार जेएलएल द्वारा जारी किया गया है। ❖ इससे पता चलता है कि भारत के टियर-1 बाजार 2.44 के समग्र स्कोर के साथ पहली बार 'पारदर्शी' क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ❖ भारत 89 देशों की सूची में 31वें स्थान पर है। ❖ उच्च पारदर्शिता क्षेत्र में 13 देश शामिल हैं। ❖ वैश्विक सूची में यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर है (1.24 के स्कोर के साथ), उसके बाद फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, जापान, बेल्जियम और सिंगापुर हैं।

खेल

ICC महिला T20 विश्व कप 2024

- ❖ ICC महिला T20 विश्व कप, जो मूल रूप से 3-20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में होना था, अब दुबई और शारजाह, UAE में आयोजित किया जाएगा।

- ❖ हरमनप्रीत कौर को ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।
- ❖ स्मृति मंधाना को हरमनप्रीत की डिप्टी बनाया गया है।
- ❖ ऋचा यास्तिका भाटिया के साथ टीम में नामित कीपर हैं।

महत्वपूर्ण समाचार- अन्य राज्य

हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' के लिए प्रतिवर्ष 53.21 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
----------------------	--

महत्वपूर्ण समाचार- दुनिया भर में

ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया नवीनतम देश है जिसने कर्मचारियों को कार्य-समय के बाद 'डिस्कनेक्ट करने का अधिकार' दिया है।
जापान	216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला शक्तिशाली तूफ़ान शानशान, अमामी द्वीपसमूह के पास पहुँचने के साथ ही दक्षिणी जापान में गंभीर व्यवधान पैदा कर रहा है। तूफ़ान के कारण भारी बारिश और खराब मौसम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण यात्रा में बड़ी बाधाएँ आई हैं।

विविध

नासा ने कई संगठनों के सहयोग से हाल ही में **टैनेजर-1** नामक उपग्रह लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष से **मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की निगरानी** के लिए बनाया गया है।

